

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 858/2005

जमील पुत्र निवाज खान, निवासी कुटुकपुर, पुलिस थाना नगर, जिला
भरतपुर। वर्तमान में उप-जेल, डीग, जिला भरतपुर में।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

लोक अभियोजक के माध्यम से राजस्थान राज्य सरकार

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री धर्मेन्द्र चौधरी
प्रतिवादी के लिए	:	श्री चित्रगुप्त चोपड़ा, लोक अभियोजक

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीर भटनागर

आदेश

आरक्षण की तिथि :: 31/01/2024

घोषणा की तिथि :: 21/03/2024

रिपोर्ट करने योग्य:

- यह मामला वर्ष 1994 में हुई एक घटना से संबंधित है और वर्तमान
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2005 से लंबित है।

2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के तहत, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2, डीग, जिला भरतपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 30/2002 में पारित दिनांक 30.08.2005 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। इस निर्णय के तहत, माननीय अपीलीय न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग, जिला भरतपुर द्वारा आपराधिक मामला संख्या 135/1996 में पारित दिनांक 15.01.1998 के दोषसिद्धि के निर्णय को बरकरार रखा है। उक्त निर्णय के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता-याचिकाकर्ता को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 के तहत छह महीने के कठोर कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, एक महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया था।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि खाद्य निरीक्षक- श्री शिखर चंद ने एक शिकायत (प्रदर्श पी-10) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 27.10.1994 को गश्त के दौरान, उन्होंने एक जमील को रोका, जो साइकिल पर दूध ले जा रहा था। दूध के बारे में पूछने पर, जमील ने बताया कि दूध भैंस और गाय का है। मिलावट के संदेह पर, उन्होंने गवाहों के सामने 6/- रुपये प्रति 750 ग्राम की दर से दूध खरीदा और एक रसीद तैयार की, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, नमूनों को परीक्षण के लिए

प्रयोगशाला भेजा गया। नमूना परीक्षण रिपोर्ट (पृदर्श पी-8) में नमूने मिलावटी पाए गए और अभियोजन स्वीकृति (पृदर्श पी-9) भी ली गई तथा इसके बाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (संक्षेप में "1954 का अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत अभियुक्त-याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा गया और शिकायत दर्ज की गई। शिकायत पर, माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा 1954 के अधिनियम की धारा 7/16 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया और आरोप तय किए गए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और परीक्षण की मांग की। पक्षों को सुनने के बाद, परीक्षण न्यायालय ने 15.01.1998 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 1954 के अधिनियम की धारा 7/16 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ता ने परीक्षण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने 30.08.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। अतः, यह याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निचली अदालतों ने आदेश पारित करने में त्रुटि की है। उनका निवेदन है कि निचली अदालतों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि अभियोजन कहानी के अनुसार, विश्लेषक रिपोर्ट 17.04.1996 को पंजीकृत डाक द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई थी,

हालांकि, निचली अदालतों के समक्ष न तो कोई पावती और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे यह पता चले कि पंजीकृत डाक याचिकाकर्ता को प्राप्त हुई थी। वह यह भी निवेदन करते हैं कि निचली अदालत ने शेर मोहम्मद (डी.डब्ल्यू.-1) के बयान पर विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता दूध बेचने के व्यवसाय में संलग्न नहीं था।

5. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि परीक्षण न्यायालय ने संक्षिप्त विचारण अपनाकर याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया है, जबकि परीक्षण न्यायालय को वारंट विचारण करना चाहिए था। वह आगे निवेदन करते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति एक नियमित तरीके से दी गई थी और इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि दिनांक 30.08.2005 और 15.01.1998 के आदेशों को निरस्त किया जाए और रद्द किया जाए।
6. विद्वान लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया।
7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. अमित कपूर बनाम रमेश चंदर और अन्य [(2012) 9 SCC 460]

के मामले में, शीर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय को धारा 397 के तहत प्रदत्त शक्तियों के दायरे पर विचार कर रहा था और उक्त निर्णय के पैरा 8 में, शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की: -

"8. वर्तमान मामले के गुणों की जांच करने से पहले हमें उस शक्ति के दायरे और विस्तार पर चर्चा करनी चाहिए, जिसका प्रयोग न्यायालय, जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, संहिता की धारा 397 और धारा 482 के तहत कर सकते हैं। संहिता की धारा 397 न्यायालय को किसी मामले में किए गए किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को मंगाने और जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य एक स्पष्ट दोष या क्षेत्राधिकार या कानून की त्रुटि को ठीक करना है। एक सुस्थापित त्रुटि होनी चाहिए और न्यायालय के लिए उस आदेश की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो अपने आप में सावधानीपूर्वक विचार का प्रतीक है और कानून के अनुसार प्रतीत होता है। यदि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखा जाए, तो यह उभर कर आता है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब किया जा सकता है जब चुनौती के तहत निर्णय घोर त्रुटिपूर्ण हों, कानून के प्रावधानों का कोई अनुपालन न हो, दर्ज किया गया निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हो, या महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा किया गया हो या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विकृत तरीके से प्रयोग किया गया हो। ये कोई संपूर्ण वर्ग नहीं हैं, बल्कि केवल सांकेतिक हैं। प्रत्येक मामले का

निर्धारण उसके अपने गुणों के आधार पर किया जाएगा।”

9. इस प्रकार, निर्धारित कानून के आलोक में, इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या क्षेत्राधिकार में कोई स्पष्ट अवैधता या त्रुटि है और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत और साक्ष्य के विरुद्ध हैं।
10. मैंने निचली अदालतों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई विकृति नहीं पाई है कि अभियुक्त याचिकाकर्ता के पास बिक्री के लिए दूध पाया गया था, जो उचित जांच पर मिलावटी पाया गया। स्वतंत्र चशमदीद गवाहों का मात्र समर्थन न होना खाद्य निरीक्षक की गवाही को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से अभियुक्त-याचिकाकर्ता के साथ पिछली दुश्मनी के किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में।
11. जहाँ तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (संक्षेप में "2006 का अधिनियम") की धारा 13 (2) के गैर-अनुपालन का संबंध है, यह स्पष्ट है कि विश्लेषक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उसकी एक प्रति अभियुक्त को उसके पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी। पता दर्शाने वाली डाक रसीद यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त को खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित सामान्य

खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत, न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि अभियुक्त को रिपोर्ट विधिवत प्राप्त हुई थी।

12. सी.सी. अलावी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद और अन्य [(2007) 6 SCC 555] के मामले में शीर्ष न्यायालय ने राय दी कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 यह अनुमान उत्पन्न करती है कि नोटिस की तामील तब प्रभावी मानी जाती है जब उसे सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, जब तक कि प्राप्तकर्ता द्वारा इसके विपरीत साबित न किया जाए, नोटिस की तामील उस समय प्रभावी मानी जाती है जिस समय पत्र सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में वितरित हो जाता। मैसर्स मदन एंड कंपनी बनाम वजीर जयवीर चंद [(1989) 1 SCC 264] के मामले में न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का विचार अपनाया गया था। इस मामले में, शीर्ष न्यायालय ने, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या मकान मालिक का कर्तव्य सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुमान के संदर्भ में नोटिस भेजकर पूरा हो गया था, यह माना कि एक बार सही पते पर मांग नोटिस का उचित निविदा हो जाने पर, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के अनुसार मांग नोटिस की तामील हो जाती है। इसी तरह, परिमल बनाम वीणा @ भारती [(2011) 3 SCC 545] के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(एफ) के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर, यह अनुमान है कि प्राप्तकर्ता

को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हो गया है। हालांकि, यह अनुमान त्रुटिहीन चरित्र के साक्ष्य पर खंडन योग्य है।

13. यह भी एक स्थापित कानून है कि सेवा के तथ्य को चुनौती देने वाले पक्ष पर अनुमान को खंडित करने का भार होता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने सेवा के तथ्य को चुनौती नहीं दी है। पंजीकृत डाक रसीद (प्रदर्श पी13) से पता चलता है कि उक्त रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पते पर भेजी गई थी और किसी विशिष्ट बचाव के अभाव में न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि अभियुक्त को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। निचली अदालतों ने अपने निर्णयों में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है। इसके अलावा, अभियुक्त ने न तो परीक्षण में कोई आपत्ति उठाई और न ही केंद्रीय प्रयोगशाला से न्यायालय के माध्यम से नमूने का विश्लेषण कराने का प्रयास किया। इसलिए, अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक विश्लेषक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, निराधार हैं। तदनुसार, मुझे अभियुक्त-याचिकाकर्ता को 2006 के अधिनियम की धारा 7/16 के तहत दोषी ठहराने वाले आक्षेपित आदेश में कोई विकृति और अवैधता नहीं मिलती है।

14. सजा में कमी के वैकल्पिक निवेदन का विश्लेषण मैसर्स ए.के. सरकार एंड कंपनी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6095/2018) दिनांक 07.03.2024 के मामले में दिए गए नवीनतम निर्णय में किया

गया था और टी. बराई बनाम हेनरी आह होए [(1983) 1 **SCC**], नेमी चंद बनाम राजस्थान राज्य [(2018) 17 **SCC** 448] और त्रिलोक चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [(2020) 10 **SCC** 763] के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित प्रावधान पर विचार करने के बाद, शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"फिर भी, उपरोक्त प्रावधान इस न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में कम सजा देने से प्रतिबंधित नहीं करता है, जब इस न्यायालय की राय है कि कम सजा दी जा सकती है क्योंकि दंडात्मक प्रावधान पर नया कानून कम सजा प्रदान करता है, अर्थात्, उस समय वास्तव में लागू होने वाली सजा से कम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित निषेध किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए उस समय लागू होने वाली सजा से अधिक सजा के अधीन करने पर है, जिस समय अपराध किया गया था। इस न्यायालय के लिए उसी अपराध के लिए अब लागू होने वाली कम सजा को लागू करने पर कोई निषेध नहीं है।"

15. टी. बराई बनाम हेनरी आह होए [(1983) 1 **SCC** 177] के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने माना कि जब कोई संशोधन अभियुक्त के लिए लाभकारी होता है, तो इसे उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है जो न्यायालयों में लंबित हैं, जहाँ अपराध के समय ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा कि: -

"22. केवल भूतलक्षी आपराधिक कानून ही अनुच्छेद 20(1) के तहत निषिद्ध है। अनुच्छेद 20(1) में निहित निषेध यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस कानून के उल्लंघन के जो अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू था, और न ही उसे उस दंड से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम नए अपराध बनाता है या किसी विशेष प्रकार के अपराध के लिए दंड बढ़ाता है, ऐसे भूतलक्षी कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही संशोधन द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ दंड लागू हो सकता है। लेकिन जहाँ तक केंद्रीय संशोधन अधिनियम अधिनियम की धारा 16(1)(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दंड को कम करता है, तो कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त को ऐसे कम दंड का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। लाभकारी निर्वचन का नियम यह मांग करता है कि इस प्रकार के भूतलक्षी कानून को भी कानून की कठोरता कम करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मजबूत तर्क और सामान्य ज्ञान दोनों पर आधारित है।"

16. उपरोक्त मामले में अभियुक्त अपीलकर्ताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 के तहत छह महीने की साधारण कारावास और प्रत्येक पर 1,000/- रुपये के जुर्माने के लिए दोषी ठहराया गया था, क्रमशः 2,000/- रुपये के जुर्माने के लिए। शीर्ष न्यायालय ने, नए अधिनियमित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दंड खंड वाली धारा 52 के प्रावधानों पर विचार करने

के बाद, अपीलकर्ता संख्या 2 की सजा को तीन महीने के साधारण कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने से 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के जुर्माने में बदल दिया और दूसरे अपीलकर्ता संख्या 1 के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा।

17. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 के तहत छह महीने के साधारण कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने के लिए दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता पर निम्न गुणवत्ता का दूध बेचने का आरोप है।
18. निस्संदेह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1976 को निरस्त कर दिया गया है और इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। निरस्त अधिनियम 1976 में मिलावट की परिभाषा धारा (i) के तहत प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार है: -

"मिलावटी" - खाद्य पदार्थ को मिलावटी माना जाएगा

-

- (क) यदि विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु क्रेता द्वारा मांगी गई प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है और उसके पूर्वाग्रह में है, या उस प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की नहीं है जिसे वह होने का दावा करती है या प्रतिनिधित्व करती है;
- (ख) यदि वस्तु में कोई अन्य पदार्थ है जो उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को

प्रभावित करता है, या यदि वस्तु को इस तरह से संसाधित किया गया है जिससे उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

- (ग) यदि किसी निम्न या सस्ते पदार्थ को वस्तु के स्थान पर पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है ताकि उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;
- (घ) यदि वस्तु का कोई घटक पूर्ण या आंशिक रूप से निकाला गया है ताकि उसकी प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;
- (ङ) यदि वस्तु को अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार, पैक या रखा गया है जिससे वह दूषित हो गई है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई है;
- (च) यदि वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी गंदे, सड़े हुए, गले हुए, विघटित या रोगग्रस्त पशु या वनस्पति पदार्थ से बनी है या कीट-ग्रस्त है या अन्यथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है;
- (छ) यदि वस्तु किसी रोगग्रस्त पशु से प्राप्त की गई है;
- (ज) यदि वस्तु में कोई जहरीला या अन्य घटक है जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है;
- (झ) यदि वस्तु का कंटेनर, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी जहरीले या हानिकारक पदार्थ से बना है जो उसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है;

- (ज) यदि वस्तु में निर्धारित रंगीन पदार्थ के अलावा कोई अन्य रंगीन पदार्थ मौजूद है, या यदि वस्तु में मौजूद निर्धारित रंगीन पदार्थ की मात्रा निर्धारित परिवर्तनशीलता सीमाओं के भीतर नहीं है;
- (ट) यदि वस्तु में कोई निषिद्ध परिरक्षक या निर्धारित सीमाओं से अधिक अनुमत परिरक्षक है;
- (ठ) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम है या उसके घटक निर्धारित परिवर्तनशीलता सीमाओं के भीतर नहीं हैं, लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है;
- (ड) यदि वस्तु की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानक से कम है या उसके घटक निर्धारित परिवर्तनशीलता सीमाओं के भीतर नहीं हैं

लेकिन जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बनाता है: बशर्ते कि, जहाँ प्राथमिक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता निर्धारित मानकों से कम हो गई है या उसके घटक निर्धारित परिवर्तनशीलता सीमाओं के भीतर नहीं हैं, दोनों ही मामलों में, केवल प्राकृतिक कारणों से और मानवीय एजेंसी के नियंत्रण से परे, तो ऐसी वस्तु को नहीं माना जाएगा

19. वर्तमान मामला पुराने अधिनियम की धारा (एम) के अंतर्गत आता है। 2006 के अधिनियम में, "मिलावट" की परिभाषा धारा 3(1)(ए) के तहत प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार है: -

(ए) "मिलावट" का अर्थ कोई भी सामग्री है जो भोजन को असुरक्षित या निम्न गुणवत्ता का या गलत ब्रांडेड या बाहरी पदार्थ युक्त बनाने के लिए उपयोग की जाती है या की जा सकती है;

20. 2006 के अधिनियम की धारा 51 में, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बेचने/भंडारण करने के लिए दंड निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार है: -

"51. निम्न गुणवत्ता वाले भोजन के लिए दंड। - कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव उपभोग के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात करता है जो निम्न गुणवत्ता का है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है।"

21. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान से यह सुस्पष्ट है कि नए अधिनियम के तहत, केवल जुर्माने का दंड निर्धारित है, इसलिए उपरोक्त संदर्भित मामलों में व्यक्त सिद्धांत को लागू करते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अपराध स्वयं वर्ष 1994 में किया गया था और तब से उनतीस और आधे वर्ष बीत चुके हैं, याचिकाकर्ता की खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/16 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा को छह महीने के साधारण कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने से 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के जुर्माने में संशोधित किया जाता है। यह राशि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय में जमा की

जाएगी। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर उपरोक्त जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय कानून के अनुसार इसे वसूलने की कार्यवाही करेगा।

22. उपरोक्त निर्देशों के साथ, पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं। मामले का रिकॉर्ड तत्काल संबंधित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।

(प्रवीर भटनागर),जे

प्रीति असोपा /32

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

